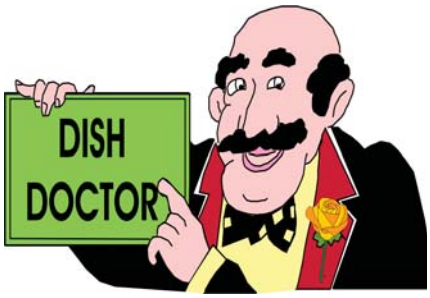

Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.

Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing,3rd Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or Email: manoj.madhavan@nm-india.com. Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Queries To: +91-91082 32956

ISSUE OF PIRACY

Q: With convergence across the broad spectrum of broadcast, cable and film, how will the industry and Govt address the crucial issue of piracy which is rampant?

Siddartha Dutta,
Kolkata, Consultant

Ans.: The broadcasting industry in India has witnessed substantial growth, driven by technological advancements and increasing consumer demand. However, this growth has also brought forth challenges such as copyright infringement and piracy, particularly in the realm of intellectual property (IP) rights.

पायरेसी का मामला

प्रश्नः प्रसारण, केबल और फिल्म के व्यापक स्पेक्ट्रम में कन्वर्जस के साथ, उद्योग और सरकार बड़े पैमाने पर व्याप्त पायरेसी के महत्वपूर्ण मुद्दे को कैसे संबोधित करेगी?

सिद्धार्थ दत्ता,
कोलकाता, सलाहकार

उत्तरः तकनीकी प्रगति और बढ़ती उपभोक्ता मांग के कारण भारत में प्रसारण उद्योग में पर्याप्त वृद्धि देखी गयी है। हालांकि इस वृद्धि ने कॉपीराइट उल्लंघन और चोरी जैसी चुनौतियों को भी सामने ला दी है, विशेष रूप से बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों के क्षेत्र में।

Copyrights in the industry pertain to cinematographic films (CF), music, advertising, web series, theatrical plays, television serials, gaming, and animation.

According to a global advisory firm, there was significant traffic to content piracy websites from India in 2022. Piracy in India involves individuals and organized groups capturing content through screen grabs or recordings in movie theaters and distributing it further. Pirated content often circulates on social media-based messaging applications, leading users to third-party pirated sites or aggregator apps not typically found on official app stores.

Piracy in the Indian film industry is estimated to cause an annual revenue loss of Rs. 20,000 crore. This illegal dissemination of video/film content not only impacts creators and theater operators but also results in losses for the government due to tax evasion.

To counter the menace of piracy, the Parliament has passed the Cinematograph (Amendment) Act, 2023. The amendments include penalties, such as a minimum of 3 months' imprisonment and fine of Rs 3 lakh, with the potential for imprisonment of up to 3 years and fine amounting to 5% of the audited gross production cost. It prohibits carrying out or abetting unauthorized recording and exhibition of films. With increase in digital penetration, piracy issues are on rise on OTT platforms, thereby imposing mounting revenue losses and reputational harm on the original creators. Illegal download options of film contents from third-party sources are available days before their release. Piracy impacts the consumption of original content through password and credential sharing, sending files over the internet, and purchasing illegal streaming devices and services which are available at just a fraction of the cost to the consumers. ■

उद्योग में कॉपीराइट सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों (सीएफ), संगीत, विज्ञापन, वेब श्रृंखला, थियेट्रिकल प्ले, टेलीविजन धारावाहिक, गेमिंग और एनिमेशन से संबंधित है।

एक वैश्विक सलाहकार कंपनी के अनुसार **2022** में भारत से कंटेंट पाइरेसी वेबसाइटों पर सबसे अधिक ट्रैफिक था। भारत में पायरेसी में व्यक्तियों और संगठित समूहों द्वारा मूवी थियेटरों में स्क्रीन ग्रैब या रिकॉर्डिंग के माध्यम से सामग्री को कैप्चर करना और इसे आगे वितरित करना शामिल है। पायरेटेड सामग्री अक्सर सोशल मीडिया आधारित मैसेजिंग एप्लिकेशन पर प्रसारित होती है जो उपयोगकर्ताओं को तृतीय पक्ष पायरेटेड साइटों या एग्रीगेटर ऐप्स पर ले जाती है जो आमतौर आधिकारिक ऐप स्टोर पर नहीं पाये जाते हैं।

अनुमान है कि भारतीय फिल्म उद्योग में पायरेसी के कारण सालाना **20,000** करोड़ रुपये के राजस्व के नुकसान होने ककी संभावना है। वीडियो/फिल्म सामग्री के इस अवैध प्रसार से न केवल मूल रचनाकारों और थियेटर संचालकों पर प्रभाव पड़ता है बल्कि कर चोरी के कारण सरकार को भी नुकसान होता है।

पायरेसी के खतरे का मुकाबला करने के लिए संसद ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम **2023** पारित किया है। संशोधनों में दंड के प्रवधान शामिल हैं, जैसे न्यूनतम **3** महीने की कैद और **3** लाख रुपये का जुर्माना, **3** साल तक के कैद की संभावना और ऑडिट की गयी सकल उत्पादन लागत का **5%** जुर्माना जैसे दंड शामिल हैं। यह फिल्मों के अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन को अंजाम देने या बढ़ावा देने पर रोक लगाता है। डिजिटल पहुंच में वृद्धि के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर पायरेसी के मुद्दे बढ़ रहे हैं जिससे मूल रचनाकारों पर राजस्व हानि और प्रतिष्ठा पर नुकसान बढ़ रहा है। तीसरे पक्ष स्रोतों से फिल्म सामग्री के अवैध डाउनलोड विकल्प उनकी रिलीज से कुछ दिन पहले उपलब्ध होते हैं। पायरेसी पासवर्ड और क्रेडेंशियल शेयरिंग के माध्यम से मूल सामग्री की खपत को प्रभावित करती है, इंटरनेट पर फाइलें भेजती हैं और अवैध स्ट्रीमिंग उपकरण और सेवाओं को खरीदती है जो उपभोक्ताओं को लागत के एक अंश पर उपलब्ध होती है। ■